श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह की बात क्यों होती है । यह बहुत गलत बात है । सभी मैम्बर बराबर हैं । यह क्या बात हुई ।

MR. SPEAKER : Order, order. He will have to resume his seat. At this rate we will not be able to cover many questions. I am sorry.

INDIANS DEPORTED FROM KENYA AND OTHER AFRICAN COUNTRIES

*601. SHRI† KANWAR LAL GUPTA:
SHRI BAL RAJ MADHOK:
SHRI SHRI GOPAL SABOO:
SHRI NATHU RAM AHIRWAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many Indians living in Kenya and in other African countries have been deported by Governments of Kenya and other African countries;

(b) if so, the number of such Indians and the reasons for their deportation;

(c) whether Government have exchanged correspondence with the Governments of Kenya and other African countries in this connection and if so, the details thereof; and

(d) the facilities given by the Government of India for their rehabilitation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). Altogether, eight persons of Indian origin were deported from Kenya in August 1966, on grounds of security. Four of these were deported to India and of these, two proceeded immediately to the U.K. There have been no further deportations from Kenya. Some persons of Indian origin in Tanzania and Malawi were last year declared prohibited immigrants and asked to leave the country.

Expulsion orders issued by the Tanzanian Government were stated to be on grounds of illegal residence in the country and the holding of irregular work permits. We approached the Tanzanian Government who agreed to review the orders issued and to revoke them in appropriate cases.

The expulsion orders issued by the Malawi Government were on grounds of security.

(c) Our High Commissioners have represented to the Governments concerned that in all cases of proposed deportation to India of persons of Indian origin who are not citizens of India, the following essential conditions must be fulfilled :—

(i) that the persons concerned should hold valid passports.

(ii) that they may not be deported to India against their wishes and that they must show a preference for being sent to India.

(iii) that the Government of India must be informed in advance in all such cases and our prior concurrence obtained to the step proposed.

Indications are that our representations have been found acceptable and that no deportation to India will be ordered in future except on the terms stipulated above.

(d) None of the deportees from Kenya have sought Government's assistance regarding their rehabilitation in India. However, when any person deported is permitted to come to India for permanent settlement the Government extends certain liberal Customs and I.T.C. concessions. These concessions include duty free entry of personal belongings as well as stocks in trade, etc. In addition, repatriates are permitted to import personal motor cars and, in some cases, where these vehicles have been in the possession of repatriates for a period of one year or more prior to their arrival, entry is permitted free of duty.

श्री कंवरलाल गुप्त : केनिया के बाद उगांडा और दूसरे अफ्रीकन देशों ने भी भारतीय ओरिजन के जो वहां के नागरिक हैं उनको और जो नागरिक वहां के नहीं हैं लेकिन जिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं या हिन्दुस्तानी पास्पोर्ट हैं उनको भी वहां से निकालना शुरू कर दिया है और इस तरह से हजारों लोगों की किस्मत अधर में लटकी हुई है, उन पर अनसरटेनटी के बादल छाये

हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सारे अफ्रीकन देशों में इस प्रकार के कितने लोग एशियन ओरिजन के हैं जिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं या इंडियन पासपोर्ट हैं तथा वहां के जो नागरिक हैं वैसे कितने लोग वहां हैं उन देशों में ।

मैं यह भी जानता हूं कि यू० के० गवर्नमेंट को जो आपने सजैशन दिया था कि पंद्रह सौ की जगह पंद्रह हजार की फिगर को वे मान लें उस सम्बन्ध में यू० के० गवर्नमेंट का लेटेस्ट रिएक्शन क्या सामने आया है ? ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्ज के बारे में आपने जो सुझाव दिया था उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है ? उस सुझाव को उन्होंने माना है या नहीं माना है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : सब कंट्रीज के आंकड़े तो मेरे पास इस वक्त नहीं हैं लेकिन ये बाद में दिये जा सकते हैं ।

जहां तक केनिया का सवाल है वहां करीब एक लाख तीस हजार आदमी ऐसे हैं जो एशियन ओरिजन के हैं जिन के पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं । जहां तक यू० के० से हुई बात चीत का सम्बन्ध है उसके बारे में हमने यह जरूर कहा था कि पंद्रह सौ आदमियों की जो लिमिट उन्होंने रखी है वह कम है और इस रफ्तार से चला जाएगा तो बरसों लग जाएंगे और कुछ सहायता नहीं मिलेगी । इसके बारे में उन्होंने कोई खास फैसला नहीं किया है और इसको उन्होंने ओपन छोड़ दिया है ····

श्री कंवरलाल गुप्त : खास का क्या मतलब है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है । हो सकता है कि आईन्दा वे इस मामले पर विचार करें और इस फिगर को बढ़ा दें । अभी वे किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह बड़े दुख की बात है और सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है कि यद्यपि यह सवाल सभी अफ्रीकन देशों के बारे में है, लेकिन अभी तक मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि हिन्दुस्तानी आरिजिन के कितने लोग वहां पर एफेक्टिव हैं और वह कह रहे हैं कि वह सूचना एकत्रित कर के देंगे । यह एक वरनिंग टापिक है, लेकिन सरकार को मालूम नहीं है कि हमारे सामने प्राबलम क्या है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इंडियन आरिजिन के लोगों के हिन्दुस्तान में आने के बारे में जो नये कर्ब्ज लगाए हैं, क्या अफ्रीका के विभिन्न देशों में स्थित हमारे हाई कमीशन्ज ने सरकार को सूचित किया है कि जन की क्या प्रतिक्रिया हुई है और कितने लोगों ने यहां आने के लिए एप्लाई किया है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : माननीय सदस्य ने पहले सवाल में जो आंकड़े मांगे हैं, वे इस लिये नहीं दिए जा सकते; (**श्री कंवरलाल गुप्त** : ये फिगर्स मैं बता सकता हूं ।) क्योंकि मूल सवाल तो डिपोटेशन के बारे में है और उनका सवाल मूल सवाल से सम्बंधित नहीं है । इस लिए उन का यह कहना कतई गलत है कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं या उस को मालूम नहीं है कि प्राबलम क्या है ।

माननीय सदस्य अपना दूसरा सवाल फिर दोहरा दें ।

श्री कंवरलाल गुप्त : सरकार ने हिन्दुस्तानी आरिजिन के लोगों के हिन्दुस्तान में आने के बारे में जो कर्ब्ज लगाए हैं, क्या अफ्रीकन देशों में हमारे हाई कमीशन्ज ने सरकार को सूचित किया है कि यहां आने वाले लोगों पर उन का क्या असर पड़ा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ लोग यहां आना चाहते हैं या नहीं और क्या किसी ने इस सम्बन्ध में परमिशन मांगी है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, असल में मूल प्रश्न से इस प्रश्न का कोई खास सम्बन्ध

नहीं है। अपने हाई कमिशनरों के साथ हमारी खतो-किताबत होती रहती है, लेकिन उस के बारे में यहां पूरी चर्चा करना ठीक नहीं होगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं ने कर्ज़ की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे हम को कुछ सुझाव देते हैं, लेकिन वे क्या सुझाव देते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि वह सब कुछ यहां बताना ठीक होगा या नहीं। इस वक्त हमारी यही कोशिश है कि जो ब्रिटिश सिटिज़न्ज़ हैं, जो ब्रिटेन वापस जाना चाहते हैं, जिस की नैशनैलैटी वे रखते हैं, उन का रास्ता किसी तरह से खुले। हम उन को सहायता देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : अफ़्रीका में केवल केनिया में ही नहीं, बल्कि यूगांडा और तन्ज़ानिया आदि देशों में भी बहुत से भारतीय बसे हुए हैं। यह ठीक है कि उन में से बहुतों ने ब्रिटिश नैशनैलेटी एक्सैप्ट करली है और इस लिए टैक्निकली उन के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन उन में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्होंने भारतीय नैशनैलेटी एक्सैप्ट कर ली है। ये इंडियन आरिजिन के लोग हैं और उन देशों में सैटल हो गए हैं, लेकिन आज उन के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उदाहरण के लिए तन्ज़ानिया की सरकार ने कहा है कि इंडियन आरिजिन के जो लड़के-लड़कियां पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, वे वापस आ जायें, वर्ना बाद में उन को वापस नहीं आने दिया जायेगा। उस देश में तो पढ़ने की उचित सुविधा है नहीं, इस कारण उन लड़के-लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा है, लेकिन इसी आधार पर उन को वहां से निकाला जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन देशों में जो इंडियन आरिजिन के लोग हैं, जिन्होंने इंडियन नैशनैलिटी एक्सैप्ट कर ली है, उन के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए, उन को न्याय दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है।" हिन्दुस्तान टाइम्स" की एक रिपोर्ट में हमारे हाई कमीशन के बारे में कहा गया है :

> ".....want to settle down in India after taking the assets and capital from here. Several such cases have been turned away by the Indian High Commission here on the ground that they have no instructions from New Delhi on such matters."

जो लोग भारत में आना चाहते हैं, जो यहां पर रुपया इनवैस्ट करना चाहते हैं, उन को भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। जो इंडियन्ज़ हमारे हाई कमीशन के पास जाते हैं, हाई कमिश्नर उन को कहते हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट ने इस बारे में कोई नीति निर्धारित की है और उस के अनुसार अपने हाई कमिश्नर को कोई इन्स्ट्रक्शन्ज़ दी हैं; यदि हां, तो क्या।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे ख्याल में डिपुटी प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में कुछ दिन पहले जवाब दिया था कि जो भारत के नागरिक हैं और यहां आना चाहते हैं, उन को पूरी सुविधा दी जाती है। उन्होंने यह भी बताया था कि उन को अपना सामान लाने, कस्टम्स और ट्रेड वग़ैरह के बारे में सहूलियत दी जाती है। जहां तक केनिया और दूसरे देशों में लोगों के डिपोर्ट होने का सवाल है, शुरू में कुछ हुए थे, लेकिन जब हम ने उन के साथ यह मामला उठाया, तब से नहीं हुए।

श्री बलराज मधोक : क्या यह सच है कि जब कुछ लोग हाई कमिश्नर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ नहीं है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं।

SHRI HEM BARUA : It is reported that two shiploads of Kenyans of Indian ancestry are coming to India and it is also reported that this Government has decided to impose visa

restrictions on the entry of those Kenyans of Indian ancestry to this country whereas the U.K. citizens are free to enter this country whenever they like. In that context, may I know whether this decision on the part of this Government to impose visa restrictions on Kenyans of Indian ancestry does not erode the Government's moral stand to criticise the British Government for adopting the Immigration Act?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: No, Sir. The hon. Member is slightly misinformed, if I may say so. The restriction is not on people of any particular origin; the restriction is on all holders of British Passports who come from Kenya, regardless of their colour or race.

SHRI HEM BARUA: My question was very specific. They might hold British Passports, but the fact remains that those Kenyans are of Indian ancestry and they want to come to this country, but visa restrictions are imposed on their entry. They are Kenyans of Indian ancestry. They might hold British Passports; that does not matter. When we impose visa restrictions like that, that corrodes and erodes our moral standard.

MR. SPEAKER: She has categorically said, British Passport holders.

SHRI HEM BARUA: They might hold British Passports, but they are of Indian ancestry.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: But they are British nationals.

MR. SPEAKER: Restrictions are there. She has said it. Shrimati Jayaben Shah.

श्रीमती जयाबेन शाह : मैं डिपोर्टेशन के असली सवाल पर आना चाहती हूं । प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अब डिपोर्टेशन नहीं हो रहा है । लेकिन दो तीन महीने पहले डिपोर्टेशन हुए थे । यह बात नहीं है कि जो लोग डिपोर्ट होते हैं, वे किसी खास कारण या वजह से डिपोर्ट किये जाते हैं, बल्कि जिन को केनिया की सरकार अपने देश में नहीं रखना चाहती है, वह उन को डिपोर्ट कर देती है । बात दरअस्ल यह है कि जिन लोगों को वह निकालना चाहती है, चाहे वे ब्रिटिश पासपोर्ट-होल्डर हों और चाहे इंडियन सिटिजन्ज़, उन को वह निकाल देती है । आज स्थिति यह है कि जो लोग डिपोर्ट किये जाते हैं, वे अपने साथ कुछ भी ला नहीं पाते हैं । गवर्नमेंट के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह उन को रीहैबिलिटेट कर सके । मैं यह जानना चाहती हूं कि जो लोग अपने साथ अपना कुछ प्रापर्टी वगैरह लाना चाहते हैं, क्या सरकार उन के लिए नियमों में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहती है या नहीं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है । उन को यहां अपना सामान लाने में मदद देने के सिलसिले में बहुत किया गया है, लेकिन किसी भी रूल में रिलैक्सेशन करते हुए हम ने यह भी देखना है कि राष्ट्र का हित क्या है । इस प्रश्न पर राष्ट्र के हित के दृष्टिकोण से और साथ ही उन लोगों को सहायता देने के दृष्टिकोण से विचार किया जाता है ।

श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात की ओर गया है कि इम्मीग्रेशन एक्ट के बारे में भारत सरकार की नीति और दृष्टिकोण हमारे दूतावासों के द्वारा वहां के लोगों को नहीं बताए गए हैं । अमरीका के उदारतावादी अखबार, **न्यूयार्क टाइम्स,** की 9 तारीख की सम्पादकीय टिप्पणी में जो आलोचना की गई है, मैं उस को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"For instance, any one reading *Times'* editorial is likely to go away with the idea that, while these U.K. citizens with Indian ancestry from Kenya would now need Indian visa to enter India, the other U.K. citizens would continue to enter India freely as in the past."

यह न्यूयार्क टाइम्स के 9 तारीख के अंक की सम्पादक की टिप्पणी है । तो मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोई इस तरह की आज्ञा या हुक्म दूतावासों को खास कर के ब्रिटिश और अमेरिकी तथा दूसरे दूतावासों को दे रही हैं कि भारत का दृष्टिकोण साफ तौर पर वहां की जनता के पास पहुंचाया जाय ताकि सम्पादकीय में जो लिखा है वैसी चीज न आये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारे दूतावासों को सब को बहुत साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं लेकिन जो दूसरे पत्रकार हैं वह हमेशा हमारे दूतावास की बातों के ऊपर नहीं चलते ।

श्री रवि राय : उस का खंडन करेंगे न ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अगर गलत है तो जरूर करेंगे ।

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: In view of our good relationship with Kenya, have Government ever thought of exercising their influence with the Government of Kenya so as to modify the immigration law and rules to the extent of not ejecting those persons who are not citizens of Kenya in large numbers? What steps are Government taking to prevent the mass eviction of those persons in Kenya who are being ejected on account of their not being citizens of Kenya?

SHRI SURENDRA PAL SINGH: This is a very recent happening. Our High Commissioner has taken up this matter with the Kenyan authorities with a view to removing certain difficulties in the way of the people who are forced to leave Kenya under these circumstances. As the House is already aware, the Prime Minister made an announcement the other day that. The Minister of State, Shri B. R. Bhagat has already gone to Kenya and he will have an opportunity of discussing this matter with the Kenyan authorities.

SHRI S. K. TAPURIAH: The hon. Prime Minister twice mentioned just now about relaxation regarding the personal luggage and things like that, and she also spoke of larger national interest. The fact is that people who want to come in here for business and industry are being harassed to a large extent. If Government relax their investment policy and invite them to invest here, about Rs. 400 to 500 crores which is lying in foreign exchange in London and Switzerland can be attracted. In this context, may I know from the Prime Minister the policy of this Government about giving relaxations to Indians in South Africa and making them come to this country for business and for investing their money?

SHRIMATI INDIRA GANDHI: We welcome the investment of their money, and the Deputy Prime Minister is looking into the matter.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: In view of the fact that these persons are holders of British citizenship and they are also of Indian origin, may I know what steps the Government of India are taking to press their claims on the British Government and to see that the number for entry into the U.K. is increased from 1500 to something more?

SHRI SURENDRA PAL SINGH: This question has already been replied to a number of times in this House. We are doing everything possible to persuade the British Government to allow more of these people to enter the U.K. We have also told them in very categorical terms that it is entirely their responsibility to make it possible for them to enter the U.K.

SOME HON. MEMBERS: *rose*—.

MR. SPEAKER: I think we can get better results after the hon. Minister of State comes back from Kenya. Now, we may go to the next question.

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: I had got up five times to ask a supplementary question but I have not been called.

MR. SPEAKER: I know. But that does not matter. There were other Members also behind him who had

been getting up. He could see only those who were getting up in the front Benches, but he could not have seen behind himself. Shri Amrit Nahata and others had also been getting up a number of times.

SHRI D. C. SHARMA : Shri Narendra Singh Mahida is sitting in front of me, and he is blocking me out completely.

MR. SPEAKER : I did not see Shri D. C. Sharma; perhaps Shri Narendra Singh Mahida's turban must have blocked the hon. Member.

Yesterday I said that I wanted to finish at least six question. If hon. Members want that we should cover a few more questions, then it is all right. Otherwise, I am personally not interested and I could go on with one question for the whole of the Question Hour. What does it matter for me ? Yesterday, I said that I wanted to finish a few more questions.

Now, let us go to the next question.

GOODWILL DELEGATIONS TO FOREIGN COUNTRIES

*602. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any assessment has been made to the effect that there is now better understanding of Indian point of view on matters of international importance, particularly the problem of Kashmir and other borders of India;

(b) whether the practice of sending delegations to foreign countries for creating good-will in favour of India, started by the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, during and after the Indo-Pak. war, is still continuing; and

(c) if so, whether a statement giving the details of the work done by delegations who visited various countries will be laid on the Table ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The assessment of the impact of our policies is a continuing process. It is Government's belief that there is now a clearer and better understanding of our point of view on a variety of questions of international importance. Our point of view on Kashmir and our differences with China are well understood.

(b) and (c). Ever since our country became independent, we have been sending delegations to foreign lands to promote better understanding of our policies and our problems in the political and cultural fields. That practice continues. A statement of the delegations sent abroad during 1966-67 and 1967-68 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-443/68.]

SHRI S. C. SAMANTA : From the statement I find that two parliamentary delegations under your leadership went to Nepal and Australia. In this connection, I would like to know whether the expenditure that was incurred has been borne by the Lok Sabha Secretariat or the External Affairs Ministry.

MR. SPEAKER : About the Lok Sabha delegations, I am told normally questions are not asked. If that is the convention—I do not know myself—I hope it will be good you follow it. There are so many other delegations going, you can ask about them.

SHRI H. N. MUKERJEE : On a point of order. I quite appreciate what you say and that is the convention as far as I know, but in that case, how does that particular item appear in the list supplied by the Ministry of External Affairs which seems to take the credit for something which is done by Lok Sabha under your direction ? It should not be done.

MR. SPEAKER : I entirely agree with the remarks of Mr. Mukerjee that it should not be included, because if it is included, naturally they ask questions. It is a part of the whole House, it is not composed of one party. Therefore, we shall continue the convention.